# ई-चार्जिंग स्टेशन का जाल बिछाएगी सरकार

## पांच एक्सप्रेसवे पर 36 ई-चार्जिंग स्टेशन के लिए आज से जमा किए जाएंगे टेंडर

**प्रदूषण से निपटने की तैयारी**

- चरणबद्ध तरीके से पीपीपी मोड पर दो हजार ई-चार्जिंग स्टेशन होंगे स्थापित

**राज्य ब्यूरो, लखनऊ :** वायु प्रदूषण से निपटने के लिए योगी सरकार ई-चार्जिंग स्टेशन का जाल बिछाने जा रही है। चरणबद्ध तरीके से पीपीपी मोड पर दो हजार ई-चार्जिंग स्टेशन सरकार स्थापित करवाएगी। प्रदेश के पांच एक्सप्रेसवे पर 36 चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के लिए ई-टेंडर शनिवार 11 नवंबर से जमा होंगे। 28 नवंबर इसकी अंतिम तिथि और 29 नवंबर को निविदा खुलेगी।

डीजल व पेट्रोल गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण को और बढ़ाता है। इसे देखते हुए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को और तेजी से बढ़ावा देने का निर्णय किया है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों वायु प्रदूषण को लेकर प्रदेश सरकार ने जो शपथ पत्र दाखिल किया उसमें भी ई-वाहनों को बढ़ावा देने के साथ ही तेजी से ई-चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की बात कही है। सरकार प्रदेश में दो हजार ई-चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करने जा रही है। इनमें आगरा, लखनऊ, प्रयागराज सहित अन्य बड़े नगरीय निकायों में 1300 ई-चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर व आगरा में ताज महल जैसे स्थलों में 100, मथुरा-वृंदावन व वाराणसी जैसे पर्यटन स्थलों पर 200 और प्रदेश के नेशनल व स्टेट हाइवे पर कुल 400 ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

प्रदेश सरकार ने केंद्र से आए निर्देशों के तहत शहरों में हर तीन किलोमीटर पर, हाइवे पर हर 25 किलोमीटर पर तथा भारी वाहन वाली रोड पर प्रत्येक 100 किलोमीटर पर पब्लिक ई-चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए काम शुरू कर दिया है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने प्रदेश में 'बैटरी स्वैपिंग' व्यवस्था के साथ पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खास बात यह है कि चार्जिंग स्टेशन के विकास के लिए चयनित आवेदनकर्ताओं को न्यूनतम लीज पर 10 वर्षों के लिए यूपीडा जमीन व कुछ आर्थिक मदद देगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर छह, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चार, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आठ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 16 व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर दो चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

## ग्रीन चैनल भुगतान योजना का बढ़ेगा दायरा, रोगियों को मिलेगी राहत

- आयुष्मान योजना में बेहतर काम करने पर अस्पतालों को इनाम

**राब्यू, लखनऊ :** आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में अच्छा काम करने वाले निजी अस्पतालों को 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान का इनाम दिया जा रहा है। ग्रीन चैनल भुगतान योजना एक वर्ष पूर्व शुरू की गई थी, 56 निजी अस्पताल इसका लाभ ले रहे थे। अब अस्पतालों की संख्या बढ़कर 1,242 हो गई है। आगे इसका दायरा और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि रोगियों को इस योजना से बेहतर उपचार की सुविधा मिल सके।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक पात्र परिवार को एक वर्ष में पांच लाख रुपये तक के निश्शुल्क उपचार की सुविधा दी जा रही है। निजी अस्पतालों में गुणवत्तापरक उपचार की सुविधा लोगों को मिले इसके लिए उनके बीच ग्रीन चैनल भुगतान योजना शुरू कर प्रतिस्पर्धा कराई जा रही है। स्टेट एजेंसी फार कांप्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज की सीईओ संगीता सिंह के मुताबिक साल भर पूर्व यह योजना निजी अस्पतालों के लिए शुरू की गई और अस्पतालों की संख्या में 22 गुणा की बढ़ोतरी हुई है।